



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1932 (श०)  
(सं० पटना 320) पटना, वृहस्पतिवार, 13 मई 2010

संख्या-३ए-३-भत्ता-०१/२००९ - ५०१५-वि.

वित्त विभाग

संकल्प

12 मई 2010

विषय:- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मंहगाई भत्ता की दरों में दिनांक 1 जनवरी 2010 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 12084 दिनांक 18 दिसम्बर 2009 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से 73 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यव विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-१(३)/२००८-III(B) दिनांक 31 मार्च 2010 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केब्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 1 जनवरी 2010 से 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार नीतिगत रूप से केब्र सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत करने का निर्णय ले चुकी है । तदनुसार केब्र सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता की दरों में संशोधन के पश्चात् राज्य कर्मियों को उक्त दर पर मंहगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है ।

4. अतः केब्रीय कर्मियों के सदृश्य अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दरों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

(क) दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व दिनांक 1 जनवरी 1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 1 जनवरी 2005

के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर 73 प्रतिशत से बढ़ाकर 87 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) मंहगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(ग) मंहगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के सम्मिलित योग के आधार पर परिणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

5. उच्च व्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य व्यायाधीश, पटना उच्च व्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रबीबद्द धर्मार,  
सचिव (संसाधन)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 320-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>